(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में कोयले की इस जरूरत को पूरा करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 19,374.07 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इस मद पर व्यय हेतु अब तक केवल 12,357 करोड़ रुपये की धनराशि का आवेटन किया है ; और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या कोयले के उत्पादन के लिये जनवरी, 1994 तक निजी क्षेत्र से कुछ प्रस्ताव भी मिले हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने प्रस्ताव हैं, उनके माध्यम से लगभग कितना उत्पादन होने का अनुमान है और सरकार ने कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) जी, हां। किन्तु कोयला तथा लिग्नाइट क्षेत्र दोनों ही के लिए आठवीं योजनावधि में योजना आयोग ने 1991-92 की कीमतों पर 12,357 करोड़ रु० का नियतन दर्शाया है। ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

करोड़ रुपये में

कम्पनी	(1991-92 की कीमतों पर)
कोल इंडिया लि०	8520
सिं०को०कं० लि० (आन्ध्र प्रदेश सरकार की इक्विटी सहित)	1050
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय अन्वेषण तथा पर्यावरण धंसाव नियन्त्रण	187
ने०लि०का०	
(क) खनन	800
(ख) विद्युत	1000
	12357

इस प्रकार आठवीं योजना अवधि में केवल कोयला क्षेत्र के लिये आवंटन 10557 करोड़ रु० की राशि का किया गया है।

(घ) और (ङ) विद्युत उत्पादन कम्पनियों तथा अन्तिम प्रयोग के लिये लौह एवं इस्पात के निर्माण में कार्यरत कम्पनियों से ग्रहीत कोयला खनन विकासार्थ अनुरोधों पर कोयला मंत्रालय द्वारा गठित एक जांच समिति द्वारा विचार किया जाता है जिसमें विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, राज्य सरकारों, कोल इण्डिया लिमिटेड, कोयला कम्पनियों आदि के सदस्य शामिल होते हैं।

विद्युत क्षेत्र के संबंध में ग्रहीत ब्लाकों का पता लगाने के लिये 15 विद्युत उत्पादन कंपनियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन विद्युत उत्पादन कम्पनियों में से 10 के ग्रहीत ब्लाकों का पता लगा लिया गया है। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में 10 कम्पनियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से तीन कम्पनियों के लिये ग्रहीत ब्लाकों का पता लगा लिया गया है। ये कम्पनियां सर्वेक्षण, खान आयोजन तथा खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए अन्य औपचारिकताएं आरम्भ करेंगे।

Augmenting output of coal during the Eighth Five Year Plan

1865. SHRI SOM PAL :

SHRI RAM NARESH YADAV :

Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether Government are planning to augment the output of coal ;

(b) if so, what are the yearwise targets for the Eighth five Year Plan period ;

(c) what measures are being adopted to achieve these targets ;

(d) what action is being taken to streamline the coal transport and delivery system : and

(e) what are the details thereof and the response thereto ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA) : (a) Yes, Sir.

(b) Planning Commission have recommended total coal production of 308 m.t. by terminal year of 8th Five Year Plan. All India coal production target for first 3 years of 8th Five Year Plan is given below :

(in million tonnes)

Year	Production target
1992-93	238.20
1993-94	249.00
1994-95	253.60

Target for year 1995-96, 1996-97 will be fixed in consultation with Planning Commission based on assessed demand and resource availability.

(c) Measure beisg taken to achieve these targets inter-alia include opening of new mines, modernisation of existing mines, application of new technology, ensuring timely availability of inputs and infrastructural facilities better capacity utilisation and maintaining good industrial relations.

(d) and (e) Due to steps taken by coal companies since nationalisation, coal transportation and delivery system have improved and grown commensurate with growth in production and despatch of coal. For improvement in transport and delivery system policy and procedure are continuously reviewed in consultation with Railways which is aimed at optimising commercial objective and consumer satisfaction in a continuously changing market scenario. Accordingly different schemes have also been introduced from time to time like liberalised sale scheme, whole sale traders scheme and mini traders scheme.

कोयला क्षेत्र में कार्य प्रणाली में सुधार

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

श्री राम गोपाल यादव :

क्या **कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक ने आगाह किया है कि अगर कार्य प्रणाली और देश में उत्पादित कोयले की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया तो सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम को बचाना मुश्किल हो जाएगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे स्वदेशी कोयले की साख समाप्त हो जाएगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भूमिगत खानों से कोयले के उत्पादन में काफी गिरावट आयी है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र में कार्य-प्रणाली में सुधार लाने के लिए देश में उत्पादित कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने और खानों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाये हैं, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) भूमिगत कोयला उत्पादन में स्थिरीकरण के कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) देश में अधिकांश भूमिगत खानें अत्यधिक पुरानी तथा विस्तृत हैं तथा समाप्त हुए भंडारों के परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता में गिरावट आई है ।

(ii) हमारे देश में भूमिगत खानें परम्परागत रूप से श्रम बाहुल्य है । अधिकांश खानों को उनके तत्कालीन स्वामियों द्वारा बिना आयोजन के बड़े पैमाने पर यंत्रिकरण के लिये खानों को विकसित किया गया था । इस स्तर पर पुनर्गठन किए जाने के लिये गहन पूंजी अपेक्षित होती है ।

(iii) विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् पिल्लर पर पड़े शेष कोयले का